संख्या–भा.स.–151/81–2–2019–800(64)/2019

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 05 अक्टूबर, 2019

विषयः–जनपद–झांसी में झांसी–बबीना–ललितपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–26 के किमी0 सं0–3 से 11 तक झांसी हंसारी से खैलार की सीमा तक दोनो पटरी पर चौड़ीकरण/चार लेन में प्रभावित 14.80 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 945 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलींगज लखनऊ के पत्र संख्या–8बी/यूपी/06/86/2019/एफ.सी/361, दिनांक 17.10.2019 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं पर की गई आपत्तियों का निराकरण कर सूचनायें एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है, जो निम्नवत हैः–

a. A proposal of 4 lane widening of NH-25 Jhansi-Lalitpur road-Babina road km 0 to 11.00 & felling of 1800 trees was submitted earlier vide online proposal no. 24768/2017 involving 28.35 ha. of Forest land. Now the fresh proposal submitted by the State Government vide online proposal no. 39827/2019 relates to 4 lanes widening of same road from km. to 11.00 involving 14.8 ha. & felling of 945 trees.
   It is not clarified whether the earlier proposal stands withdrawn by the State Government or not?
b. It is also not clarified –
   (i). Why the original proposal has been modified or why a new proposal has been submitted.
   (ii). what will be the outcome if NOC of Ministry of Defiance is not obtained. Issued and what is the alternative available for the user agency to complete the project and how does it affect the viability of the project.
c. The Forest offence has been compounded after taking compensation but calculation of Penal NPV payable as per recent guidelines of the Ministry dated 29-01-2018 is not correct as penalty has not been calculated for each year of violation. This needs rectification.
d. In area calculation sheet, uniform width of proposed widening has been taken. It is not clear whether extra width is required at culverts, bridges etc. and to what extent requirement of Forest area increases in that case.

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संलग्न पत्र दिनांक 17.10.2019 में उल्लिखित कमियों का निराकरण कर सूचना/तत्सम्बन्धी अभिलेख शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
उप सचिव।

Data D. SO.Nodal.GO